further says that 35 other rivers have also been identified under this scheme. What is the stage of the Ganga Action Plan? The Minister says that it is Phase-1. Are there any more phases? Then what is the stage of other 35 rivers? I would also like to know about the stage of Ganga Action Plan. How much is the allocation of funds given under this scheme? What is the timeframe?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Regarding the Ganga, first and second mainstream rivers, towns covered — 73; States covered — 5. We have sanctioned Rs. 1026 crores and the amount released by the Government of India is Rs. 825 crores. The total number of schemes sanctioned for the Ganga is 572, out of that 445 have been completed. The work is going on. We are releasing funds to the State Governments as per the DPRs.

श्री कमाल अख्तर: शुक्रिया सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि गंगा अभी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। उसमें जितना भी प्रदूषण होता है, वह उसमें मिलने वाली नदियों या नालों से होता है। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 20 राज्यों में 164 शहरों की 35 नदियों की पहचान की गई है जो उसको प्रदूषित कर रही हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार से जब गंगा निकलती है तो अगर सबसे पहले उसमें पॉल्यूशन होता है तो वह गजरौला की औद्योगिक इकाइयाँ, जो बगद नदी के अंदर पड़ती हैं, उनसे होता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 164 शहरों में इन 35 नदियों की पहचान की है, क्या उनमें बगद नदी भी शामिल है?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Whether a particular river is there or not, I will give this reply to the hon. Member. But the NRCP work is going on. Sir, I will send the reply to the Member.

श्री कमाल अख्तर: सर, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर Half-an-Hour discussion हो चुका है। अभी प्रधान मंत्री जी की ओर से — उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। अगर जिस नदी से सबसे पहले पॉल्यूशन हो रहा है, उसी नदी को नहीं लिया जाएगा — मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसे नहीं लिया गया है। मैं अनुरोध करूँगा कि मंत्री जी उसको ले लें।

श्री नमो नारायण मीणा: आपको हमने पहले बताया कि Ganga River basin को cover करने की revamping scheme चल रही है, जो भी गंगा की tributaries होंगी, अगर इसमें नहीं हैं, they will all be covered.

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, I will not make a statement. I will straight away come to the supplementary.

In the context of what is being discussed, would the Government seriously consider implementation of the old proposal, of linking the major rivers of the country, of what was popularly called as Garland Canal Project? Bringing the waters of Ganges right up to Cauvery, it will have an effect of reducing the river pollution.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, it is a good supplementary. But the hon. Minister should address it to the concerned Minister.

बी.पी.एल. निर्धारण संबंधी मापदंड

*244. **डा. मुरली मनोहर जोशी**:††
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

††सभा में यह प्रश्न श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी द्वारा पूछा गया।

(क) क्या यह सच है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में मापदण्ड निर्धारित करने के लिए एक डालर प्रतिदिन की आय के बजाय अब 1.25 डालर और 1.35 डालर प्रतिदिन की आय दर को मापदण्ड मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या इस समय भारत में भी उपर्युक्त मापदण्ड का अनुसरण किया जा रहा है; और

(ग) इस मापदण्ड के आधार पर भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कितनी कमी आने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विश्व बैंक के शाओहुआ चैन एवं मार्टिन रॉवलियन द्वारा अगस्त, 2008 में 'नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर सं. 4703 के शीर्षक' "विकासशील विश्व हमारी सोच से अधिक निर्धन, फिर भी गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में काफी सफल" के अंतर्गत प्रकाशित शोधपत्र में लेखकों ने (2005 की कीमतों पर) 1.00, 1.25, 1.45, 2.00 और 2.50 डालर की गरीबी रेखाओं के समनुरूप हैडकाउंट सूचकांक (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता) और गरीबों की संख्या दी है। पेपर के निष्कर्ष पूर्णत: लेखकों के अपने हैं और वे निश्चित रूप से विश्वबैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अत:, 1.25 डालर की गरीबी रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर लगाए गए गरीबी अनुमानों का प्रयोग नहीं करती है। योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता और संख्या का अनुमान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच-वर्षों के अंतराल पर कराए जाने वाले घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में निहित पद्धति का प्रयोग करते हुए लगाता है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी में कमी का अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के स्थान पर प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग गरीबी रेखाओं के आधार पर लगाया गया है। योजना का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 10 प्रतिशतता बिन्दु तक उपभोग गरीबी के हैडकाउंट अनुपात को कम करना है।

Criteria for determining the BPL

†*244. SHRI MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several international financial institutions have now adopted the limit of income at the rates of 1.25 and 1.35 dollars per day, instead of one dollar a day, for determining the criteria in regard to people living below poverty line;

(b) if so, the facts thereof and whether at present the above criteria are being followed in India; and

(c) The expected decrease in the number of people living below poverty line in India on the basis of the above criteria during the Eleventh Plan?

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by [MURLI MANOHAR JOSHI].

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In a 'Policy Research Working Paper No. 4703' entitled 'The Developing World is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty' by Shaohua Chen and Martin Ravallion of the World Bank released in August 2008, the authors have given the Head Count Index (percentage of population living below poverty line) and the number of poor corresponding to poverty lines (in 2005 prices) of $1.00, $1.25, $1.45, $2.00 and $2.50. The findings of the paper are entirely those of the authors and they not necessarily represent the views of the World Bank. As such, there is no reference to poverty line of $1.35. Government of India does not use poverty estimates based on international poverty lines. The Planning Commission estimates the percentage and number of persons living below the poverty line at national and state level, separately in rural and urban areas from the large sample survey on household consumer expenditure conducted by the National Sample Survey Organization (NSSO) at an interval of approximately five years following the methodology contained in the Report of the Expert Group of Estimation of Proportion and Number of Poor.

(c) The extent of poverty reduction during the Eleventh Five Year Plan has been projected on the basis of the poverty lines which is different in the rural and urban areas of each State, instead of international poverty line. The Plan targets to reduce the headcount ratio of consumption poverty by 10 percentage points during the five year period of the Eleventh Plan.

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य रखा है, उससे कुछ बात साफ नहीं होती। भारतवर्ष में गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हैं, गरीबी की आय का निर्धारण किस हिसाब से किया जाता है, ये सवाल इसमें से उठ रहे हैं। क्योंकि, पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि 1999 और 2000 की कीमतों पर All India level पर जो गरीबी रेखा है, वह 327.56 रुपए प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 454.11 रुपए प्रति माह शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दिल्ली में 15-16 रुपए रोज कमाते हैं तो आप गरीबी की सीमा के नीचे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन 15-16 रुपए में कौन सा consumption हो सकता है? आदमी खाना भी नहीं खा सकता। आप calorie intake के हिसाब से निर्धारित करते हैं, लेकिन वह खाना नहीं खा सकता, वह कपड़े नहीं पहन सकता, वह जूते नहीं पहन सकता, वह बच्चों को क्या खिलाएगा, क्योंकि 15 रुपए तो उसकी कुल आमदनी है। तो आपने यह जो गरीबी की रेखा का निर्धारण किया है इसका मतलब क्या है और फिर आप किस रास्ते से उसको निर्धारित कर रहे हैं? आप सिर्फ sample survey करवाते हैं, उनका मतलब क्या है, वे किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं? इसमें एक बात यह भी है कि क्या आप inflation के हिसाब से इसको भी एडजस्ट करते हैं और क्या आपने अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट का अध्ययन किया है? अपने एक माननीय सांसद की यह रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो यह गरीबी की सीमा के साथ सरकार मज़ाक क्यों कर रही है? आप यह दिखाना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ 25-26 करोड़ गरीब हैं, असलियत को क्यों छिपाना चाहते हैं? इस देश की सच्चाई सामने आने दीजिए, जो गरीबी पिछले 60 साल में हम नहीं मिटा सके हैं, वह देश के सामने आ जानी चाहिए और प्लानिंग कमीशन वगैरह की जो सारी विफलताएं हैं, वे देश के सामने आ जानी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Let your supplementary be answered.

डा0 मुरली मनोहर जोशी: इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्पष्ट बात बताएं कि देश में गरीबी की सीमा को निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए, आपने जो मानदंड अभी तक बनाए हैं, क्या वे सही हैं और उनके आधार पर देश में गरीबों की संख्या कितनी होनी चाहिए?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. senior Member has put a very long list of supplementaries relating to poverty line. Sir, the poverty line in our country is being assessed on the basis of household consumption expenditure by every household. And it is not on the basis of dollar rate that is prevailing at the international market...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I have not said it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: He is not answering the supplementary put by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt. ...*(Interruptions)*... Allow the supplementary to be answered.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I have just started the reply. The Government appointed a committee under Dr. D.T. Lakadwala. He went into the suggestions made by the Expert Group. The Expert Group submitted its Report to the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAY SINGH: When was it?

SHRI V. NARAYANASAMY: That was in 1997. They submitted a report. Sorry; it was 1993. The Report was submitted in 1997. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, what is this? The hon. Minister should give us the correct date. He should give us one date. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Saab, this is not helping matters.

डा. मुरली मनोहर जोशी: सर, यह क्या हो रहा है? Sir, the House cannot be held to ransom like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am just answering. The National Sample Survey Organisation does the survey. On the basis of the survey, they submit a report to the Planning Commission. Sir, I would like to submit that the percentage of the number of the people living below the poverty line at the national and State level, in urban and rural areas, is being worked out in our country. It is not like the western countries. Sir, the hon. Member wanted to know about the percentage of this. According to 2004-05. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, I have asked. ...*(Interruptions)*... Sir, this is not fair. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Saab, you have to ask the second supplementary also ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, the hon. Minister has every right to reply, but not a right to confuse the House. If he has the right to confuse, then, we are getting nowhere with this. ...*(Interruptions)*... What is this? ...*(Interruptions)*... The hon. Minister cannot confuse the country.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, यह बीपीएल fraud है ...(**व्यवधान**)...**।**

MR. CHAIRMAN: Please *...(Interruptions)...* Please, your turn is coming.

SHRIMATI BRINDA KARAT: It is the destitution line. *...(Interruptions)...* It is the destitution line. *...(Interruptions)...* It is a shame for our country.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, the hon. Minister must make a clearcut reply. Sir, I have asked a very specific question. I have not said that it is just on the basis of the western countries. I have said that you judge it on the basis of the calorie intake. I said that you have judged it on the basis of the sample survey. On that basis, I have asked certain question. Please answer them directly. *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am answering them. *...(Interruptions)...* Sir, there is a confusion on the question of poverty line. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: By that time, the Question Hour will be over.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I would like to clarify that the poverty line is different and assessing the poor is different. That is being done by the Rural Development Ministry. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he is confusing the House.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, what is this? Sir, he is again confusing the House. *...(Interruptions)...*

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, इस विषय पर special discussion करवा दिया जाए ...(**व्यवधान**)...**।**

SHRI V. NARAYANASAMY: Have the patience to hear me. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please, let the Minister reply. *...(Interruptions)...*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, the Planning Commission says one thing; the Ministry of Health says something else. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: This is not fair. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* The Leader of the House wishes to intervene.

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, यह गंभीर मसला है, इसलिए इस पर special discussion होना चाहिए...(व्यवधान)...।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, there are several ways in which poverty can be measured, and particular reference was made to the World Bank Study which is a Report by two distinguished scholars. That is not the methodology which is used by the Planning Commission. We have, every five years, a large sample of the National Sample Survey. That is the basis for calculating the consumption poverty on the head count basis, and that is the poverty line which is in terms of the basket of goods and services which would enable a person to consume 2400 calories in the rural areas and 2100 calories in the urban areas. As prices change, this is also taken into account.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It means that you don't take into account any other consumption, except the calories. *...(Interruptions)...* But, the human body does not only consume calories, he has to clothe himself, he has to provide something to his family also, and

not even to the family, the basic requirement of medicines for him, and then, education for himself and his children, the house rent, electricity, etc. What should, therefore, be the total consumption? Is it calorie alone? ...*(Interruptions)*... Is it calorie alone?

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, there can be, I think, many measures of poverty. I am not saying that this is the only measure of poverty, but this has been a measure which has been certified by an expert committee under Prof. D.T. Lakadwala. Further, refinements are possible, and Dr. Suresh Tendulkar Committee is looking into this matter.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I would like to ask of the Prime Minister, through you, would he agree that the quantification of the poverty line today of 329 rupees in the rural areas per adult is a fraud on the poor people of this country because the entire Government's policy of providing benefits to the poor is linked to this. And if he agrees that 329 rupees in a growing economy is a fraud, what is the Prime Minister doing to change it?

MR. CHAIRMAN: I am afraid, the Question Hour is over.

———————

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Growth rate in the country

†*245. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the annual growth rate in the country is expected to remain between 8 per cent and 7 per cent in the financial year 2008-09;

(b) if not, the estimated rate;

(c) whether it is also a fact that the annual growth rate in the foodgrain and industrial manufacturing sector is expected to remain lower than the average growth rate;

(d) if so, the facts thereof;

(e) whether it is also a fact that the increase in average growth rate depends on the increase in service sector, which in turn depends on international powers; and

(f) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) and (b) As per the estimates released by the Central Statistical Organisation of Ministry of Statistics and Programme Implementation, the growth rate of the economy, measured in terms of Gross Domestic Product at factor cost, was 7.8 per cent in the first half (April-September) of the financial year 2008-09 over the corresponding period of the previous year. Projections of growth for the full year 2008-09 vary considerably because of uncertainty about the depth and

†Original notice of the question was received in Hindi.